

न्यूज़ टुडे

शून्य—बजट प्राकृतिक खेती (Zero-budget natural farming: ZBNF) से आंध्र प्रदेश के किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ है

- एक अध्ययन के दौरान धान, मूँगफली आदि जैसी फसलों में ZBNF और गैर-ZBNF तकनीकों की तुलना करके निष्कर्षों को प्राप्त किया गया था। तुलना करने के लिए जल, विद्युत, ऊर्जा की खपत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, उपज और शुद्ध राजस्व इन 6 मापदंडों को आधार बनाया गया था।
- ZBNF से धान की कृषि के दौरान प्रति एकड़ 1,400 से 3,500 क्षयूविक भीटर जल की बचत हुई है। यदि भारत के संगूण धान के कृषि क्षेत्रों को ZBNF के तहत लाया जाता है, तो इससे संभवतः 150–400 बिलियन क्षयूविक भीटर तक जल की बचत हो सकती है।
- भौमजल पर निर्भर खेतों की विद्युत की खपत प्रति एकड़ 1,500–3,900 यूनिट कम हुई है और इससे 6,000–16,000 रुपये तक की बचत भी हुई है।
- ZBNF ने रोगाणुओं की गतिविधियों को अवरुद्ध किया है और भीथेन उत्सर्जन में 88% तक की कटौती की है।
- अध्ययन से भी यह ज्ञात हुआ है कि इस तकनीक का फसल की उपज पर कोई विशेष प्रभाव परिलक्षित नहीं हुआ है।
- ZBNF पारंपरिक भारतीय कृषि प्रथाओं से व्युत्पन्न रसायन मुक्त खेती पर आधारित एक विधि है। इसे मूल रूप से महाराष्ट्र के एक कृषि विशेषज्ञ सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित किया गया था। ZBNF को केंद्रीय बजट 2019–20 में प्रस्तुत किया गया था।
- ZBNF 4 तरंगों (इकोग्राफिक देखें) पर आधारित है।
- ZBNF के लाभ: इसमें रासायनिक खेतों की तुलना में जल और विद्युत की अत्यल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, यह स्व-स्थाने (in-situ) संसाधनों का उपयोग करके कृषि की लागत को कम करती है तथा मृदा के पोषण एवं उर्वरता व कीटों और बीजों का प्रबंधन करती है।

राज्यों के लिए व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business: EODB) रैंकिंग जारी की गई

- इसका प्रकाशन राज्यों में समग्र व्यावसायिक परिवेश में सुधार करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department of Industrial Promotion and Internal Trade: DPIT) द्वारा किया गया है। वर्ष 2015 से आरंभ होने के उपरांत यह इसका चौथा वार्षिक संस्करण है।
- वर्ष 2019 हेतु राज्यों की रैंकिंग, व्यवसाय सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan:BRAP) के कार्यान्वयन पर आधारित है।
 - DPIT द्वारा जारी किए गए BRAP 2018-19 में 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्रों जैसे कि सूचना तक पहुंच, सिंगल विडो सिस्टम (Single Window System), श्रम, पर्यावरण आदि को शामिल करने वाले 180 सुधार बिंदु शामिल हैं।
- श्रेणीवार रैंकिंग: टॉप अचौर्वस (Top Achievers) (95 प्रतिशत से अधिक अनुपालन); अचौर्वस (Achievers) (90–95 प्रतिशत); फास्ट मूर्वर्स (Fast Movers) (80–90 प्रतिशत) तथा एस्पायर्स (Aspirers) (80 प्रतिशत से कम)।
- वर्ष 2019 की रैंकिंग के निष्कर्ष
 - आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है, इसके उपरांत उत्तर प्रदेश का स्थान है।
 - ❖ उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत से आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत से पश्चिम बंगाल, पश्चिम भारत से मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत से असम शीर्ष स्थान पर रहे। वहीं संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
- त्रिपुरा 36वें स्थान पर (अंतिम स्थान पर) रहा।
- यह रैंकिंग व्यवसाय-उद्यमों के संदर्भ में सरकारी विनियामक कार्यों की वर्धित पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ राज्यों में EODB को अभिव्यक्त करती है।
 - राज्यों की रैंकिंग निवेश को आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में EODB में वृद्धि करने में सहायता करेगी।

चंद्रयान-1 द्वारा प्रेषित चित्र चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव को इंगित करते हैं

- प्रेषित चित्र प्रदर्शित करते हैं कि अपने ध्रुवों पर चंद्रमा जंग लगा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसके अतिरिक्त, चंद्रयान-1 के डाटा से संकेत प्राप्त हुआ है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर जल विद्यमान है।
 - चूंकि चंद्रमा की सतह लौह समृद्ध चट्टानों के लिए जानी जाती है, परन्तु वहां जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति ज्ञात नहीं है। इसलिए नासा (NASA) का मानना है कि इसके लिए पृथ्वी का वातावरण आंशिक रूप से उत्तरदायी हो सकता है।
- चंद्रयान-1 के बारे में
 - इसे वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके साथ 11 वैज्ञानिक उपकरण संलग्न थे, जिनका निर्माण भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन और बुलारिया में किया गया था।
 - ❖ भारत से पेलोड (नीतिमार): भू-खंड (Terrain) मैपिंग कैमरा, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर, लूनर लेजर रेंजिंग उपकरण, हाई एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर तथा मून इम्पैक्ट प्रोब।
 - ❖ विदेशों से पेलोड: चंद्रयान-1 एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, नियर इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, सब केवी (keV) एटम रिफ्लेक्टिंग एनालाइजर, मिनिएचर सिथेटिक एपर्चर रडार, मून मिनरलोजी मैपर तथा रेडिएशन डोज मॉनिटर।
 - इसका उद्देश्य खनिज और रासायनिक तत्वों के वितरण के संदर्भ में संपूर्ण चंद्र सतह के रासायनिक तथा खनिज-संबंधी मानवित्रण का संचालन करना है।
 - प्रमुख निष्कर्ष: अल्प मात्रा में वाष्प के रूप में विद्यमान जल का पता लगाया, ओशन मैग्मा परिकल्पना की पुष्टि की, अशक्त सौर चमक के दौरान एक्स-रे संकेतों का पता लगाया, जिससे चंद्रमा की सतह पर मैनीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन और कैल्सियम की उपस्थिति का संकेत प्राप्त हुआ है।
 - केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया है कि चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण वर्ष 2021 के आरंभ में हो सकता है।

ZERO BUDGET NATURAL FARMING

involves four components...

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ One, 'beejamrutham', or microbial coating of seeds using cow dung and urine based formulations | <ul style="list-style-type: none"> ■ Three, mulching, or applying a layer of organic material to the soil surface, to prevent water evaporation and contribute to soil humus formation |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Two, 'jeevamrutham', or application of a concoction made with cow dung, cow urine, jaggery, pulse flour, water and soil, to multiply soil microbes | <ul style="list-style-type: none"> ■ Four, 'waaphasa' or soil aeration through favourable micro climate in the soil |

भारत और ईरान के रक्षा मंत्रियों की तेहरान में बैठक हुई

बैठक के प्रमुख परिणाम

- व्यापार पर: व्यापार और वाणिज्य के विविधीकरण एवं विस्तार तथा अधिमान्य व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement: PTA) को शीघ्रतापूर्वक संपन्न करने के संबंध में वार्ता की गई।
- अफगानिस्तान पर: अफगानिस्तान के शासन को रिश्तर बनाए रखने हेतु भारत व ईरान को सम्मिलित करते हुए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के पुनर्स्थापन पर चर्चा की गई। ज्ञातव्य है कि अमेरिका अफगानिस्तान से प्रस्थान करने व तालिबान को अफगान शासन में हिस्सेदार बनाने की योजना निर्मित कर रहा है।
- ❖ इससे पूर्व, जब तालिबान वर्ष 1996–2001 के दौरान सत्ता में था तब रूस, भारत और ईरान ने नॉर्डैर्न अलायंस का समर्थन करके अपने हितों की रक्षा के लिए सहयोग किया था।
- ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध: ईरान ने भारत से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अपने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान निष्पक्ष रूख अपनाने की अपेक्षा की है।
- भारत के लिए ईरान का महत्व
 - खाड़ी क्षेत्र में नौ मिलियन भारतीय निवास करते हैं और ईरान भारत की व्यापक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।
 - ईरान परिस्तान को उपेक्षित कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया का प्रवेश द्वारा है। इसके अतिरिक्त, ईरान अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (International North-South Transport Corridor) का एक महत्वपूर्ण भागीदार राष्ट्र भी है।
 - ईरान खाड़ी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है।
- हालिया मुद्रे
 - ईरान ने चाबहार-ज़ाहेदान रेलवे अनुबंध 'खतम अल-अन्बिया कंस्ट्रक्यूशंस' (Khatam al-Anbiya constructions) को प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की है।
 - ❖ यह इकाई अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों के अधीन है, जिसका अर्थ है कि जो भी कंपनी इसके साथ व्यापारिक समझौता करेगी उसे भी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
 - ईरान में चीन की घुसपैठ बढ़ रही है।
 - ईरान के विरुद्ध अमेरिकी प्रतिबंध भारत-ईरान साझेदारी, विशेषतया व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा विज्ञापनों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Under Consumer Protection Act, 2019) के तहत, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) को अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- > इन दिशा-निर्देशों में आकार, प्रारूप या माध्यम पर ध्यान दिए बिना सभी विज्ञापन और विषयन संचार को समाविष्ट किया गया है।
- प्रमुख दिशा-निर्देश:

 - > असर्वीकरण (disclaimers) देतु: यदि कोई विज्ञापन एक साधारण उपभोक्ता के लिए सरलतापूर्वक ध्यान देने योग्य, सुपार्च व समझने योग्य नहीं है, तो उसे भ्रामक विज्ञापन (misleading advertisements) माना जाएगा।
 - > पृष्ठांकक (Endorser) देतु: वे सभी विवरण, दावे और तुलनाएं जिन्हें किसी विज्ञापन में पृष्ठांकित किया जाता है अथवा जो विज्ञापन में प्रदर्शित किए जाते हैं, वे यह प्रकट करने में सक्षम हों कि वे निष्पक्ष रूप से अभिनिश्चित किए गए हैं और वे प्रमाणित भी हैं।
 - > सरोगेट (Surrogate) विज्ञापन पर: जिन वस्तुओं या सेवाओं का विज्ञापन अन्यथा प्रतिबंधित है, वे अन्य वस्तुओं या सेवाओं (जिन्हें निषिद्ध नहीं किया गया है) के विज्ञापन द्वारा ऐसे प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेंगे।
 - > निःशुल्क दावों पर: यदि किसी उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के दौरान लागत के अतिरिक्त और कुछ भी भुगतान करना पड़ता है, तो इस संदर्भ में संबंधित विज्ञापन में उक्त वस्तु या सेवा को मुफ्त, निःशुल्क अथवा किसी अन्य समान पदावली के रूप में वर्णित नहीं किया जाएगा।
 - > प्रलोभन (Bait) देने वाले विज्ञापन पर: किसी भी विज्ञापन के माध्यम से, जिसमें प्रत्युत मूल्य वाली विज्ञापित किसी वस्तु अथवा सेवा के विक्रय का कोई तार्किक उद्देश्य निहित नहीं है, उसे क्रय करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रलोभित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा।

अन्य सुर्खियाँ

केशवाननंद भारती (Keshavananand Bharati)	<ul style="list-style-type: none"> ○ वे केरल के कासरगोड जिले में स्थित इडनीर मठ के प्रमुख थे। ○ केशवाननंद भारती वाद में ही पहली बार उच्चतम न्यायालय (SC) द्वारा संविधान के मूल ढांचे को निर्धारित किया गया था। > यह वाद मुख्य रूप से संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के दायरे से संबंधित था। ○ उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संविधान का मूल ढांचा अनुलंगनीय है अर्थात् संसद द्वारा संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता।
K-शेप रिकवरी (K-shaped recovery)	<ul style="list-style-type: none"> ○ K-शेप एक काल्पनिक शब्द है, जो अमेरिका में कोरोना के कारण व्याप्त मंदी को इंगित करने हेतु जो विडेन द्वारा सूजित किया गया है। यह संदर्भित करता है कि जो शीर्ष पर हैं वे आर्थिक लाभ को बनाए रखने में सक्षम बने हुए हैं। इसके विपरीत, जो मध्य एवं निम्न पायदान पर हैं, वे प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं या निम्नतर स्थिति की ओर अग्रसर हैं। ○ भारत में इसका एक उदाहरण स्टॉक मार्केट है, जो लाखों लोगों की नौकरी की क्षति होने के बावजूद भी बेहतर स्थिति में बनी हुई है। ○ इसी प्रकार की असमानताएं रोज़गार क्षेत्र में भी मौजूद हैं। अल्प-कुशल श्रमिकों के रोज़गार में अनुपातहीन तरीके से गिरावट आई है, जबकि वित्तीय एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों पर यह प्रभाव अत्यंत सीमित रहा है।
पिदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act: FCRA)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इस वर्ष गृह मंत्रालय द्वारा चार ईसाई संगठनों के FCRA लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है। ○ किसी भी गैर-लामकारी संगठन को विदेशों से धन (फंड) प्राप्त करने हेतु FCRA लाइसेंस रखना अनिवार्य होता है। ○ FCRA वस्तुतः व्यक्तियों या संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की स्वीकृति और उपयोग के विनियमन में सहयोग करता है तथा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध किसी भी गतिविधि में इसके उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (Start-up Village Entrepreneurship Programme: SVEP)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भिशन के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना की एक उप-योजना है। इसका उद्देश्य महिलाओं सहित ग्रामीण परिवर्तनों को नए उद्यम (स्टार्ट-अप) स्थापित करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना एवं उनकी सहायता करना है। > SVEP के तहत ग्रामीण स्टार्ट-अप के तीन प्रमुख स्तंभों को निर्मित करने का प्रयास किया गया है, जैसे – वित्त, इनक्यूबेशन और कौशल पारिस्थितिक तंत्र। ○ इसका दीर्घकालिक लक्ष्य 1 करोड़ ग्रामीण उद्यमों को स्टार्ट-अप के लिए सहायता उपलब्ध करवाना तथा 2 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करना है। > अगस्त 2020 तक, लगभग 1 लाख उद्यमों को समर्थन दिया जा रहा है, जिनमें से 75% उद्यम महिलाओं के स्वामित्वाधीन और उनके द्वारा प्रबंधित हैं।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा शिक्षा पर जारी एक रिपोर्ट एवं संबंधित डेटा (Data from a report on education released by the National Statistics Office (NSO))	<ul style="list-style-type: none"> ○ रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: <ul style="list-style-type: none"> > साक्षरता में शीर्ष 5 में शामिल राज्य/संघ शासित प्रदेश हैं: केरल (उच्चतम— 96.2%), दिल्ली, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश व असम। > निम्न 5 में शामिल हैं: उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश (सबसे कम — 66.4%) > 84.7% पुरुष साक्षरता और 70.3% महिला साक्षरता के साथ अखिल भारतीय स्तर पर पुरुष-महिला साक्षरता का अंतराल 14.4% रहा है। > सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में एक वृहद पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधोंने हेतु उत्तराधीनी है।
पहला "इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज़" (First ever International Day of Clean Air For Blue Skies)	<ul style="list-style-type: none"> ○ संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2019 में प्रत्येक वर्ष 07 सितंबर (वर्ष 2020 से प्रारम्भ) को "इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज़" आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। ○ इसके उद्देश्यों में शामिल हैं: > सभी स्तरों पर जन-जागरूकता बढ़ाना। > अन्य पर्यावरणीय/विकासात्मक चुनौतियों [जैसे— जलवायु परिवर्तन और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs)] का वायु गुणवत्ता से घनिष्ठ संबंध अर्थात् इन गतिविधियों से वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को प्रदर्शित करना। > वायु की गुणवत्ता में सुधार करने वाले उपायों को बढ़ावा देना और उन्हें सुविधाजनक बनाना। > एक रणनीतिक गठबंधन निर्मित करने हेतु विविध अंतर्राष्ट्रीय अभिकर्ताओं/हितधारकों को एक साथ लाना।
अरब सागरीय जल का तापन (Warming Arabian Sea)	<ul style="list-style-type: none"> ○ वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर के असामान्य तापन के कारण इस वर्ष अगस्त माह में भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक मानसूनी वर्षा हुई है। ○ पूर्व की रिपोर्टों में यह इंगित किया गया था कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अरब सागर के उष्णता अर्थात् तापन में वृद्धि हुई है। ○ चूंकि अरब सागर के तापन से मानसूनी पवनों की अनियमितता में वृद्धि हुई थी तथा अरब सागर से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अधिक आद्रेता का प्रवाह हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी धाट और मध्य भारत में अत्यधिक वर्षा हुई है।
मालावार विद्रोह (Malabar rebellion)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह वर्ष 1921 में केरल के मणिला (मोपला) मुस्लिमों द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों और उनके अलोकप्रिय जैमियों (जमीदारों) (जिनमें से अधिकतर हिंदू थे) के विरुद्ध प्रारंभ किया गया एक साशस्त्र विद्रोह था। ○ यह खिलाफत आंदोलन का एक हिस्सा था और इसे मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। > मोपला मुख्यतः निर्धन कृषक थे। ○ इसे प्रायः दक्षिण भारत में राष्ट्रवादी विद्रोह की शुरुआती घटनाओं में से एक माना जाता है। ○ ब्रिटिश सरकार द्वारा इस विद्रोह से निपटने के लिए अत्यंत कठोर कदम उठाए गए थे। इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए गोरखा रेजिमेंट को तैनात किया गया था तथा साथ ही मार्शल लॉ भी लागू किया गया था।